बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 213

निजीकरण ही उपाय

केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को लेकर निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों का विलय किया जाएगा और दिल्ली तथा मुंबई में संचालित एमटीएनएल, तब तक बीएसएनएल की अनुषंगी होगी। वर्ष 2019-20 के बजट के मुताबिक दोनों कंपनियों को आंतरिक तथा बाहरी बजट संसाधनों से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटानी थी। इस पैसे को बॉन्ड जारी करके जुटाया जाएगा जिसकी भरपाई सरकारी कंपनियां करेंगी लेकिन इनकी गारंटी केंद्र सरकार देगी। जाहिर है यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है क्योंकि बीएसएनएल खुद भारी घाटे में है। अकेले 2018-19 में इस सरकारी कंपनी को 14,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसके साथ ही उसका समेकित घाटा 90,000 करोड़ रुपये का स्तर पार कर गया। एमटीएनएल की बैलेंस शीट में 20,000 करोड़ रुपये का घाटा है।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार वाकई यह मानती है कि इन कंपनियों को दूरसंचार क्षेत्र में उपयोगी योगदान करने वाली कंपनियों में शामिल किया जा सकता है। सकारात्मक पहलू देखें तो इन सरकारी कंपनियों के पास करीब 70,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य की जमीन है। परंतु इन कंपनियों को लेकर नकारात्मक बातों की भी कमी नहीं है। मिसाल के तौर पर भारी भरकम वेतन बिल। बीएसएनएल और एमटीएनएल के 200,000 कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बहुत धनराशि व्यय होती है। बीएसएनएल की बात करें तो उसके खर्च का 77 फीसदी हिस्सा वेतन में जाता है। मंत्रिमंडल ने जिस पुनरुत्थान योजना को मंजूरी दी है उसमें अपेक्षा की गई है कि आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज के चलते अगले पांच से सात वर्ष में बड़ी तादाद में कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेंगे। बीएसएनएल ने सरकार से 4जी स्पेक्ट्रम की प्रशासित कीमत के बराबर की इक्विटी डालने को भी कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मानना है कि 4जी स्पेक्ट्रम की कमी ने उसे निजी 4जी कारोबारियों के समक्ष गैर प्रतिस्पर्धी बना दिया है।

दूरसंचार क्षेत्र में बहुत तेज गति से बदलाव होते हैं। यहां तक कि पहले से कारोबार कर रहे निजी कारोबारियों को भी हालिया प्रवेश करने वाली रिलायंस जियो से निपटने में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यह क्षेत्र व्यापक बुनियादी ढांचे वाला कारोबार कम और सेवा प्रदाता कारोबार अधिक है। इस प्रतिस्पर्धा में निजी क्षेत्र हमेशा बाजी मार लेता है क्योंकि वह सरकारी उपक्रमों की तुलना में ग्राहकों के अधिक अनुकूल होते हैं। यह उन कारोबारियों के साथ भी बड़ा अन्याय है जिन्होंने भारी कर्ज लेकर स्पेक्ट्रम खरीदा और इस क्षेत्र में उन सरकारी उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धा बरकरार रखी जिन्हें स्पेक्ट्रम नियंत्रित मूल्य पर मिलता है और जिनके सामने बजट की भी ज्यादा चुनौती नहीं होती। एयर इंडिया को लगातार सरकारी सहयोग से हवाई उड़ानों के बाजार में विसंगति उत्पन्न हुई और इसके चलते अब एक नहीं बल्कि दो पूर्णकालिक विमान सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। क्या सरकार दूरसंचार क्षेत्र में कभी यही करना चाहती है? उसे तथ्यों के अनुसार काम करना चाहिए। बीएसएनएल और एमटीएनएल को करदाताओं के पैसे से मुनाफे में नहीं लाया जा सकता। अगर ऐसा हुआ भी तो इससे बाजार में बुरी विसंगति उत्पन्न होगी और निजी कारोबारी कारोबार से बाहर हो जाएंगे। इससे कमोबेश सबका नुकसान होगा। इन कंपनियों का पुनरुत्थान करने के बजाय इनका निजीकरण करना आवश्यक है।

अजय मोहंती

प्याज के आंसुओं की अंतहीन गाथा

भौगोलिक विविधीकरण, पूर्व चेतावनी व्यवस्था और सूखे प्याज के विकल्पों को बढ़ावा देने से अगली बार प्याज के संकट से निपटने में मदद मिलेगी। बता रहे हैं **रमेश चंद** और **राका सक्सेना**

देश में एक बार फिर प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले दस साल में यह तीसरा मौका है जब प्याज की कीमतें बेकाबू हुई हैं। मई और जून में प्याज थोक बाजार में 10 रुपये प्रति किलो और खुदरा बाजार में 20 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रहा था लेकिन अब देश के अधिकांश बाजारों में इसकी थोक कीमत 35 रुपये किलो और खुदरा कीमत 60 रुपये किलो के पार पहुंच गई है। किसी भी फसल की अंतर-वर्ष मूल्य अस्थिरता और अंतर -वर्ष असामान्य कीमत से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को नुकसान होता है और साथ ही अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसे देखते हुए कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव को जानने और इसके समाधान के लिए व्यावहारिक विकल्प ढूंढना जरूरी है।

कीमतों में बार-बार असामान्य उछाल से भारतीय उपभोक्ताओं के व्यवहार में एक दिलचस्प बदलाव का खुलासा होता है। इस पर चर्चा करने से पहले प्याज उत्पादन के रुझानों और देश में इसकी उपलब्धता पर नजर डालनी जरूरी है। हाल में दिनों में प्याज सबसे तेजी से बढ़ने वाली फसल रही है। 2004-05 से 2018-19 के दौरान इसकी सालाना वृद्धि दर 10 फीसदी रही जबकि घरेलू उत्पादन 64.3 लाख टन से बढ़कर 2.349 लाख टन पहुंच गया। 2004-05 में इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता 5.15 किलो थी जो 2018-19 में तीन गुना बढ़कर 15.7 किलो पहुंच गई। खाद्य पदार्थों के मामले में प्रति व्यक्ति खपत के हिसाब से देश में प्याज के बाद खाद्य तेल का स्थान है। जाहिर है कि भारतीय तेजी से मसालेदार और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों का रुख कर रहे हैं जबकि सरकार का लक्ष्य पोषाहार को बढ़ावा देना है।

यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि प्याज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भारी बढ़ोतरी के बावजूद, इसकी मात्रा में थोड़ी कमी से ही कीमत में भारी उछाल आती है। यह औसत भारतीय के खपत व्यवहार में बदलाव और इसे संभालने की व्यवस्था में कमी की ओर इशारा करता है। हालांकि प्याज देश के लोगों का मुख्य आहार नहीं है और इसका इस्तेमाल शोरबा बनाने और सलाद में किया जाता है। लेकिन इसकी भारी मांग से साबित होता है कि लोग इसकी खपत में कमी को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उपभोक्ता इसका इस्तेमाल छोड़ने के बजाय सामान्य कीमत से तीन-चार गुना दाम देने को तैयार हैं। सामाजिक दबाव के कारण भी लोग प्याज की खपत नहीं घटाना चाहते हैं। वे ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं कि बढ़ी कीमत के कारण वे प्याज नहीं खा रहे हैं।

हाल के हफ्तों में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण उत्पादन में कमी है। महाराष्ट्र देश में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और यहीं से इसकी कीमत तय होती है। राज्य के कुछ हिस्सों में सूखे जैसे हालात के कारण रबी के पिछले मौसम में प्याज का रकबा बहुत घट गया था। इस कारण राज्य में प्याज के सालाना उत्पादन में 9.11 फीसदी की कमी आई। यही वजह है कि नेफेड ने जून में रबी की फसल के तैयार होने के बाद प्याज की रिकॉर्ड खरीद की ताकि सितंबर से नवंबर में कम आपूर्ति के दौरान प्याज की कीमतों को संभाला जा सके। खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली प्याज की दूसरी फसल महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बरबाद हो गई। प्याज के उत्पादन में कमी की आशंका के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

पिछले वर्षों की तरह इस बार भी सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ने पर व्यापारियों के लिए प्याज की भंडारण सीमा तय की और इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया पहले कदम का मकसद इसकी जमाखोरी रोकना है और दूसरे का लक्ष्य निर्यात के लिए जा रही फसल को घरेलू बाजार की तरफ मोड़ना है। कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है जो इसकी मूल्य की स्थिति को समग्रता के साथ नहीं देखते।

खाद्य पदार्थों के व्यापार में मामले में भारत और अधिकांश अन्य देश मुक्त व्यापार के बजाय रणनीतिक उदारीकरण की नीति का पालन करते हैं। इस नीति में उत्पादन की कमी से निपटने के लिए आयात को उदार बनाया जाता है और निर्यात प्रतिबंधित किया जाता है। दूसरी ओर बंपर फसल होने पर इसका उलटा होता है यानी आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

इस नीति के मुताबिक किसानों को कम कीमत से बचाने के लिए अक्सर कृषि और खाद्य जिंसों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हालांकि उपभोक्ताओं को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मौजूदा स्थिति उपभोक्ता के हित में है क्योंकि तीन महीने की कम अवधि में प्याज की कीमतें तीन गुना बढ़ गई हैं। कीमतों में बढ़ोतरी से उन किसानों को मोटा मुनाफा हुआ है जिन्होंने अपनी रबी की फसल बेचने का इंतजार किया। नवंबर में बाजार में खरीफ की फसल आनी शुरू होगी या कीमतें सामान्य होंगी, तो निर्यात पर से प्रतिबंध हटने से किसान प्रभावित नहीं होंगे।

कीमतों में बार-बार उतार-चढ़ाव और मांग एवं आपूर्ति की मौजूदा स्थिति से भविष्य में मूल्यों को स्थिर रखने के लिए कई सबक मिलते हैं। पहला सबक यह कि प्याज की कीमतों में कमी के लिए पूरे साल इसकी निरंतर आपूर्ति की जरूरत है। हालांकि उत्पादन में उतार-चढ़ाव आ सकता है। कीमतों को स्थिर रखने के लिए सार्वजनिक भंडारण पर निर्भरता जरूरी है। हम निजी क्षेत्र से भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि कीमतों में किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव से निजी क्षेत्र को फायदा होता है। अगर नेफेड ने कीमत स्थिरीकरण कोष के रूप में 53,000 टन प्याज की खरीद नहीं की होती तो इसकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई होतीं। इसमें से महाराष्ट्र से 45.53 हजार टन प्याज खरीदा गया था जिसे बाजार में उतारा गया। देश को मौसमवार उत्पादन और मांग के मुताबिक रबी और खरीफ के मौसम के अंत में प्याज का उचित भंडार रखना चाहिए। यह न केवल उपभोक्ताओं बल्कि किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा।

साथ ही कच्चे प्याज के विकल्प के रूप में प्रसंस्कृत उत्पादों जैसे निर्जलित प्याज और प्याज पेस्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक उपाय यह है कि देश के प्याज उत्पादन का आधार बहुत कम है और इसमें महाराष्ट्र का एक-तिहाई योगदान है। मौसम में अनियमितताएं बढ़ रही है जिससे भविष्य में उत्पादन में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका है। भौगोलिक विविधीकरण और कुछ नए इलाकों में प्याज की खेती, खासकर उत्तरी राज्यों में खरीफ के मौसम में प्याज उगाने से उत्पादन में उतार-चढ़ाव और कीमतों में अस्थिरता पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही अलग-अलग इलाकों के अनुकूल प्याज की किस्में विकसित करने की जरूरत है ताकि बाजार में हर मौसम में प्याज की आपूर्ति बनी रहे। इसके अलावा प्याज के बारे में बाजार के खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है और एफएओ की चेतावनी व्यवस्था की तर्ज पर पूर्व समायोजन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इस व्यवस्था के तहत अगले सत्र में अनुमानित कीमतों के बारे में किसानों को परामर्श जारी किया जाना चाहिए ताकि वे उसके हिसाब से रकबा घटा-बढ़ा सकें। इन उपायों से देश में प्याज के आंसुओं के चक्र को रोका जा सकता है।

(चंद नीति आयोग के सदस्य हैं। सक्सेना राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में प्रधान अर्थशास्त्री हैं। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं।)

वैश्विक रैंकिंग में नहीं दिखती मोदी सरकार की कड़ी मेहनत

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

भारत के मौजूदा सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी चिंता जाहिर करने वाले नागरिकों पर 'देश की छवि खराब करने' का आरोप बहुत जल्द लग जा रहा है। इसी से जुड़ा एक और आरोप यह होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार प्रदर्शन को कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में वापस ली गई राजद्रोह याचिका हमें इस पर यकीन दिला देती। मोदी के प्रति आस्था का पुरजोर बचाव करने वालों को यह समस्या हो सकती है कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय संस्थान ही इस छवि को कमतर और धूमिल करने में लगे हुए हैं।

मोदी और शी चिनफिंग की मामल्लपुरम में मुलाकात के ऐन पहले और बाद में तीन संस्थानों ने भारत का आर्थिक वृद्धि अनुमानों को अधिक प्रभावी नहीं रहने की बात कही है। हाल में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान 6.2 फीसदी से घटाकर 5.8 फीसदी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस सुस्ती के कई कारक हैं जो मुख्यत: घरेलू और आंशिक रूप से दीर्घकालिक हैं।

इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की नई प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा ने भारत और ब्राजील का नाम लेते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में समकालिक सुस्ती सबसे ज्यादा इन्हीं देशों में नजर आ रही है। हाल ही में आईएमएफ ने इस वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर अनुमान को सात फीसदी से घटाकर 6.1 फीसदी कर दिया है। इसके बाद विश्व बैंक ने वृद्धि अनुमानों में तगड़ी कटौती करते हुए 7.5 फीसदी से भारी गिरावट के साथ महज छह फीसदी कर दिया है। इसके पहले एशियाई विकास बैंक और फिच ने भी वृद्धि अनुमानों को घटा दिया था।

इस खबर के बाद संपादकीय पृष्ठों पर बांह मरोड़ने या शोरशराबे वाले टीवी शो में हंगामा खड़ा होने के मौके कम ही आए हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर ये संस्थाएं ही इस विमर्श के पीछे हैं। आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वालों को पहले से ही इन बुरी खबरों का अंदेशा था। आरबीआई ने वृद्धि अनुमान को 6.9 फीसदी से घटाकर 6.1 फीसदी कर और उच्च तीव्रता वाले संकेतकों में कटौती कर इसकी चेतावनी बहुत पहले दे दी थी। पहली तिमाही के पांच फीसदी वृद्धि दर के आंकड़े बेहद आशावादी बजट अनुमानों को गलत बताते हैं और दूसरी तिमाही में इसके बदतर होने की आशंका है। और अपने दैनिक जीवन में वृद्धि दर की सुस्ती का असर झेलने वाले भारतीयों को पहले से ही इसका अहसास होने लगा है।

गिरते आंकड़ों को लेकर चिंतित ये संस्थान 'देश की छवि खराब करने' में अकेले नहीं हैं। विभिन्न संस्थानों की तरफ से जारी होने वाली वैश्विक रैंकिंग से भी यही लगता है कि 'मोदी का प्रभावी प्रदर्शन' देख पाना मुश्किल है। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक पर नजर डालें तो भोजन के अधिकार का व्यापक एवं खर्चीला कानून होने के बावजूद भारत को इस सूची में असरदार स्थान नहीं मिला है। वर्ष 2010 में 95वें स्थान पर रहा भारत इस सूचकांक में 2019 में 102वें स्थान पर है।

वर्ष 2000 में भूख सूचकांक में 83वें स्थान पर रहे भारत का प्रदर्शन लगातार गिरा है। इन दिनों सार्वजनिक विमर्श को निर्धारित करने वाले व्हाट्सऐप संदेशों की भावना को देखें तो यह कहना सही है कि गरीब-समर्थक कही जाने वाली संप्रग सरकार का प्रदर्शन भी खास अच्छा नहीं था। लेकिन इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि उसके बाद सत्ता में आने के लिए मोदी ने विकास के काम अभूतपूर्व तेजी से संपन्न कराने का वादा किया था। कद के अनुपात में कम वजन वाली आबादी 2008-12 के दौरान 16.5 फीसदी थी लेकिन 2014-18 की अवधि में यह 20.8 फीसदी पर जा पहुंची। इस पैमाने में भारत ने यमन और जिबूती को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में विकास के चुनावी वादों की सच्चाई पर सवाल उठने लाजिमी हैं।

मानव विकास के महत्त्वपूर्ण पैमाने उच्च शिक्षा पर मोदी सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की खास नजर कई तरह से बनी रही है। हालांकि इस साल 2012 के बाद पहली बार कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 300 संस्थानों की टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह नहीं बना पाया है। समग्र मानव विकास के मोर्चे पर हालात शायद ही बेहतर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2014 रिपोर्ट में 188 देशों में से 135वें स्थान पर रहने वाला भारत 2018 में 189 देशों में से 130वें स्थान पर रहा।

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और तमाम घोषित सरकारी कार्यक्रम भारत को औद्योगिक रफ्तार देने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में वैश्विक धारणा के मामले में भारत की रैंकिंग में उछाल आनी चाहिए थी। लेकिन विश्व आर्थिक मंच की तरफ से जारी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक में भारत 10 पायदान गिरते हुए 141 देशों में 68वें स्थान पर आ गया है। इस गिरावट का कारण यह नहीं है कि भारत ने निर्धारित मानकों पर खराब प्रदर्शन किया है, बल्कि दूसरे देशों का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा।

हालांकि भारत ने उन तीन सूचकांकों में सुधार दर्ज किया है जो मोदी की प्राथमिकता में ऊपर रहे हैं। कारोबारी सुगमता सूचकांक में दो साल के भीतर 53 स्थानों की छलांग लगाते हुए भारत 2018 में 190 देशों में से 77वें स्थान पर रहा। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भी 2018 में भारत तीन स्थान के सुधार के साथ 180 देशों में से 78वें स्थान पर रहा। वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में भारत पांच साल के भीतर 29 स्थान की छलांग लगाते हुए 129 देशों में से 52वें स्थान पर आ गया। कारोबारी सुगमता सूचकांक के तीन पैमानों पर उल्लेखनीय प्रगति के साथ शीर्ष 25 देशों में आ चुका है। लेकिन भारत को 'औसत मध्यम' दर्जे में डालने वाले इन सुधारों को शानदार कहना अतिशयोक्ति ही होगी। यह बात हमें दुनिया बता रही है, 'राष्ट्रद्रोही' भारतीय नहीं।

कानाफूसी

सिंधिया की नाराजगी

कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी की सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि खानेपीने की चीजों में मिलावट के आरोपियों को सरकार बिना समुचित कार्रवाई के छोड़ दे रही है। सिंधिया ने जहां यह बात कही वहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद थे। सिंधिया ने इशारा किया कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मामले बंद किए जा रहे हैं और मंत्री को इसकी खबर तक नहीं लग रही है। पहले पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री का चयन करते वक्त उनकी अनदेखी की और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम की घोषणा करने में भी देरी कर रही है। यही कारण है कि सिंधिया एक के बाद एक सरकार पर हमले करके दबाव बना रहे हैं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने किसान ऋण माफी का वादा पूरा न करने के लिए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया था।

अध्ययन सामग्री

जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाली संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने कई ऐसे विषयों का चयन किया है जिनका वह अध्ययन करेगी। समिति ने अध्ययन के लिए जिन 15 विषयों का चयन किया है उनमें मुद्रास्फीति को निशाना बनाने वाली नीतियों और मौद्रिक पारेषण, निगरानी की गुणवत्ता और वित्तीय संस्थानों की निगरानी, ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता तथा जीडीपी को एक लाख करोड़ डॉलर का आकार देने जैसे विषय भी शामिल हैं। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार में सिन्हा वित्त राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्री थे।

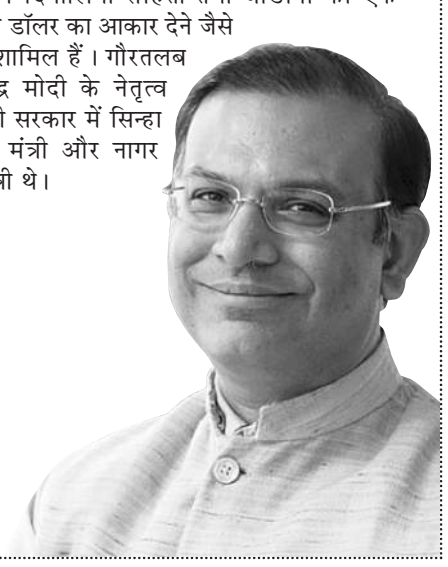

आपका पक्ष

गरीबी रेखा का पैमाना तय हो

भारत में अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजार रहे हैं। पूर्व एवं वर्तमान सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाने के बावजूद गरीबी पूरी तरह से नहीं हट पाई है। योजना आयोग ने कई समितियों का गठन कर गरीबी की गणना एवं गरीबी की पद्धति का मापदंड तय करने के लिए कहा था। देश में गरीबी रेखा न्यूनतम उपभोग खर्च के आधार पर तय की जाती है। अलघ समिति द्वारा कैलरी उपभोग की संकल्पना के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी का क्रमश: 2,400 एवं 2,100 कैलरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन स्वीकार किया गया। तेंडुलकर समिति ने कैलरी का उपयोग छोड़ देने की सिफारिश की एवं अन्न, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कपड़े इत्यादि वस्तुओं पर होने वाले खर्च पर गरीबी रेखा तय की। लेकिन तेंडुलकर समिति द्वारा उपयोग में लाई गई गरीबी गणना की पद्धति की आलोचना की गई। इसके बाद सरकार ने रंगराजन समिति का गठन किया। रंगराजन

समिति ने दोबारा अन्न एवं गैर अन्न वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग खर्च के आधार पर गरीबी रेखा एवं उसका प्रमाण को गिनने के लिए सिफारिश की। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी के लिए क्रमश: 2,155 और 2,090 कैलरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन लिया। लेकिन सरकार ने इस समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पर आने के बाद नीति आयोग की पहली बैठक में अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। लेकिन इस समिति ने नई गरीबी रेखा सूचित करने के बजाय इसके लिए दूसरी समिति स्थापित करने की सिफारिश की। इसका अर्थ यह है कि सरकार अब तक गरीबी रेखा का आधार तय करने में और उसका उचित मापदंड का हल खोजने में असमर्थ रही। तेंडुलकर समिति के अनुसार देश में 21.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, बल्कि रंगराजन समिति की गरीबी मापने के अनुसार 29.6 प्रतिशत लोग गरीब हैं। देश की योजनाएं अगर उचित वर्गों एवं जरूरतमंदों तक पहुंचाना है तो सरकार का यह दायित्व है कि वह गरीबी रेखा का आधार एवं उसका मूल्यांकन के गणित का हल खोजे।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

देश में गरीबी खत्म करने के लिए सरकार को उचित नीति बनाने की जरूरत है

कौशल युक्त शिक्षा की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी क्षेत्रों में कौशल युक्त श्रम की जरूरत होगी जिससे विकास की गति तेज होगी। कामकाजी आबादी की उम्र के मामले में भारत की स्थिति अन्य प्रतिस्पर्धी देशों से बेहतर है। अत: आज बड़ी चुनौती युवाओं को रोजगार प्रदान करने की है। ऐसे में सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, वाणिज्य, कानून आदि क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। शिक्षा पूरी करने वाले युवाओं को शुरुआती स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना जरूरी है। कौशल विकास में बढ़ोतरी कर लोगों को कौशल युक्त बनाना होगा। असंगठित क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2030 तक बुजुर्गों की संख्या बहुत सारे विभागों में देखने को मिलेगी। ऐसे में सरकार को सभी क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

संगीता चौधरी, जयपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।